पत्रांक–भवन / बजट–65–योजना(विधि विभाग)–02 / 2022–23.........................

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सचिव–सह–विधि परामर्शी,
विधि विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः–

विषयः– **केन्द्र प्रायोजित योजना– BR43 Development of Infrastructure Facilities for Judiciary(9174) अंतर्गत परियोजनाओं की विवरणी न्याय विकास पोर्टल पर अपलोड एवं अपडेट किये जाने तथा परियोजनाओं के प्राथमिकता निर्धारण के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–5286 दिनांक–07.07.2026 तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार के पत्रांक–11017/03/2021-JR (Part 1)(E-8427) दिनांक–24.06.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधि विभाग से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना– BR43 Development of Infrastructure Facilities for Judiciary (9174) अंतर्गत न्याय विकास पोर्टल पर परियोजनाओं की विवरणी अपलोड / अद्यतन किये जाने, परियोजनाओं के प्राथमिकता निर्धारण तथा संबंधित ई–भुगतान वाउचर की विवरणी अपलोड किये जाने हेतु निदेशक अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है (संबंधित विवरणी संलग्न)। उल्लेखनीय है कि न्याय विकास पोर्टल में तकनीकी त्रुटि के कारण योजनाओं की विवरणी अपलोड एवं अपडेट किये जाने में कठिनाई हो रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत किये जा रहे निर्माण कार्यो की विवरणी न्याय विकास पोर्टल में अपलोड एवं अपडेट किये जाने में हो रही तकनीकी समस्या के निराकरण कराने की कृपा की जाय।

अनु०ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 6800 (अ)अनु   पटना, दिनांक– 22/7/26

प्रतिलिपि:–मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो की विवरणी न्याय विकास पोर्टल पर अपलोड एवं अद्यतन किये जाने तथा CFMS 2.0 के SNA SPARSH Module अंतर्गत भुगतान हेतु विपत्र समर्पित किये जाने के उपरांत विपत्र की विवरणी न्याय विकास पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कृपा की जाय।

22/7/26

सरकार के अपर सचिव।

पत्र संख्या–जी0/यो0–31–80/2019 5286/जे0,

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 07.7.26

विषयः– **Introduction of New Functionalities on Nyaya Vikas Portal-Prioritization of Projects and Submission of E-payment-regarding.**

प्रसंगः– अवर सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली का पत्रांक–J-11017/03/2021-JR(part-1)(E-8427), दिनांक–24.06.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि न्याय विकास पोर्टल पर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की विवरणी अद्यतन करने और संबंधित ई–भुगतान वाउचर को अपलोड किये जाने हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रसंगाधीन पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि न्याय विकास पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए विवरणी विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली को उपलब्ध कराते हुए विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

B.S. Mehrotra 06.07.26

(बासनो शंकर मेहरोत्रा)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

D:\Prem Prakash\Ajay JI-1\G.Yo1.Doc